THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV) : (a) and (b) The Government has liberalised licensing policy for spinning mill. Replacement of spindles by Rotors and Air Jet units has been allowed to help boost production of yarn and such modernisation is eligible to be financed under the Textile Modernisation Fund Scheme of Industrial Development Bank of India.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिये गठित कृतिक बल की बैठकें

1724. **श्रीमती सरला माहेश्वरी:**
श्री नारायण कार:

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिये गठित कृतिक बल की तिमाही पुनरीक्षा बैठकें विदेशों में आयोजित की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं, जहां अब तक इस प्रकार की बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ग) क्या इन बैठकों पर होने वाला लाखों रुपये का खर्च विदेशी परामर्शदात्री फर्मों अथवा भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है; और

(घ) इन बैठकों को भारत में आयोजित करने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं?

इस्पात और खान मंत्री साथ में विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री दिनेश गोस्वामी): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अनुसार इस प्रकार की बैठकें उनके कुछ प्रमुख ठेकेदारों के मुख्यालयों में इन ठेकेदारों की कार्यविधियों, जो इन फर्मों द्वारा अपने मुख्यालय में कार्यान्वित की जा रही हैं, की प्रगति की समीक्षा के लिए की गयी थीं। अभी तक मेसर्स मैनेसमन डिमाग हटेन्टेक्निक के मुख्यालय पश्चिम जर्मनी में डुइसबर्ग में तथा मेसर्स त्याजप्रोमेक्स पोर्त के मुख्यालय सोवियत संघ रूस स्थित मास्को में बैठकें की गयी हैं। ये फर्में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण परियोजना के संबंध में प्रमुख ठेकेदार हैं। इन बैठकों में शामिल होने वाले सेल के अधिकारियों के सम्बन्ध में हुए खर्च को "सेल" द्वारा वहन किया जाता है।

"सेल" के अनुसार इस प्रकार की बैठकों का आयोजन परियोजना की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

India's Contribution to Asian Development Bank

1725. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was India's contribution to the Asian Development bank as on 31st March, 1990;

(b) what is the figure relating to the amount of borrowing as on that date; and

(c) when the borrowings commenced?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) $176,715 million.

(b) $1773.50 million, including equity/ loans of $25.90 million to private sector.

(c) 1986.

Foreign Tours by Chairmen of Nationalised Banks

1726. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Chairmen of the nationalised banks are often visiting foreign countries;

(b) if so, what are the details in respect of visits of each of the Chairman of different banks along with the purpose of each visit during the last two years, year-wise; and

(c) whether it is also a fact that non-productive expenses of the banks are constantly increasing and if so, what steps have been taken to reduce such expenditure of the banks?

THE DEPUTY MINISTER IN THE

MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c) The information is being collected and to the extent available will be laid on the Table of the House.

छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक निर्मित की गई सिंचाई क्षमता

1727. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अंत (1984-85) तक बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं द्वारा निर्मित की गई सिंचाई क्षमता कितनी है;

(ख) क्या निर्मित की गई क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है; यदि नहीं, तो सिंचाई क्षमता का उपयोग किस सीमा तक किया जा रहा है और कितनी का उपयोग किया जाना है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के अंत (1984-85) तक छोटी सिंचाई परियोजनाओं द्वारा निर्मित की गई सिंचाई क्षमता कितनी है और किस सीमा तक इस प्रकार की सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया): (क) और (ख) छठी योजना तक 30.01 मि०हे० सिंचाई क्षमता वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित की गयी थी, जिसमें से 25.33 मि०हे० के उपयोग की सूचना प्राप्त हुई। 4.68 मि०हे० क्षमता उपयोग नहीं की गयी।

(ग) लघु सिंचाई के अन्तर्गत 37.52 मि०हे० क्षमता सृजित की गई थी, जिसमें से 35.25 मि०हे० के उपयोग की सूचना प्राप्त हुई।

Employment of Persons who were Displaced due to the Setting up of Visakhapatnam Steel Plant

1728. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) how many persons are yet to be employed in Visakhapatnam Steel Plant who were displaced at the time of the setting up of this project;

(b) how many of them have already been given employment; and

(c) what is the target date for completing the recruitment process?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES WTTH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI DINESH GOSWAMI): (a) to (c) Visakhapatnam Steel Project had committed to give employment to 5,000 displaced persons, subject to their being found suitable, by the time the project is fully operational. Out of these, 4,589 persons have already been given employment. As such, 411 more displaced persons are yet to be given jobs.

Introduction of Cadi Credit System for Farmers by Andhra Bank

* 1729. DR. YELAMANCHILI SIVAJI. WiU the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Andhra Bank has introduced Cash Credit System for fanners in Guntur District of Andhra Pradesh; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) and (b) Andhra Bank has reported that it has introduced Agricultural Cash Credit System on a pilot project basis initially in Guntur district of Andhra Pradesh during the current year. Apart from simplifying the documentation procedure and speedy disbursal of loan, the procedure of cash credit system will create a confidence in the beneficiary that to the extent of sanctioned limit, he can draw amounts as per his requirement any time based on the cropping pattern he adopts and he can repay as and when he gets some income to reduce the burden of interest. Under the scheme, the credit requirements of farmers will be worked out for each crop season and an